



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

7 श्रावण 1944 (श10)  
(सं0 पटना 570) पटना, शुक्रवार, 29 जुलाई 2022

सं0 08/आरोप-01-69/2015-11059/सा0प्र0  
सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प

5 जुलाई 2022

श्री सुनील दत्त झा, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक-739/2011, तत्कालीन अंचलाधिकारी- सह-प्रखंड विकास पदाधिकारी, रहिका, मधुबनी के विरुद्ध इंदिरा आवास के निर्माण में अनियमितता बरतने, अपने कर्तव्यों में लापरवाही बरतने तथा कार्यो का पर्यवेक्षण नहीं करने संबंधी आरोपों के लिए ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 234640 दिनांक 10.06.2015 द्वारा आरोप पत्र अनुशासनिक कार्रवाई हेतु प्राप्त हुआ।

ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना द्वारा प्रतिवेदित आरोप पत्र की प्रति संलग्न करते हुए विभागीय पत्रांक-10247 दिनांक 15.07.2015 द्वारा उनसे स्पष्टीकरण की मांग की गयी। उक्त के आलोक में पत्रांक 112 दिनांक 13.02.2017 द्वारा श्री झा का स्पष्टीकरण प्राप्त हुआ। श्री झा से प्राप्त स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक 4805 दिनांक 24.04.2017 द्वारा जिला पदाधिकारी, मधुबनी से मंतव्य की मांग की गयी। स्मारोपरांत जिला पदाधिकारी, मधुबनी के पत्रांक 62 दिनांक 24.01.2022 द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराया गया। प्राप्त मंतव्य में आरोप संख्या-01, 02 एवं 04 के संबंध में साक्ष्य/बयान के अभाव में विभागीय स्तर पर निर्णय लिये जाने, आरोप संख्या-03 के संबंध में स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य नहीं तथा आरोप संख्या-05 के संबंध में स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य प्रतिवेदित किया गया।

तदुपरांत सम्यक् विचारोपरांत ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना से प्राप्त आरोप के आधार पर विभागीय स्तर पर आरोप पत्र पुनर्गठित करते हुए अनुशासनिक प्राधिकार के अनुमोदनोपरांत विभागीय पत्रांक 5207 दिनांक 04.04.2022 द्वारा श्री झा से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। उक्त के आलोक में श्री झा द्वारा अपना स्पष्टीकरण (दिनांक 30.05.2022) समर्पित किया गया। जिसमें उनके द्वारा अपने उपर लगाये गये आरोपों से इन्कार करते हुए आरोप मुक्त करने का अनुरोध किया गया।

श्री झा के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप, उनके प्राप्त स्पष्टीकरण एवं उनके स्पष्टीकरण पर जिला पदाधिकारी, मधुबनी से प्राप्त मंतव्य की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर की गयी। समीक्षोपरांत पाया गया कि जिला पदाधिकारी, द्वारा अपने मंतव्य में आरोप सं०-01,02, एवं 04 के संबंध में साक्ष्य/बयान के अभाव में विभागीय स्तर पर निर्णय लिये जाने तथा आरोप सं०-05 को स्वीकार योग्य प्रतिवेदित किया गया है। आरोप सं०-05 के संदर्भ में आरोपित पदाधिकारी के स्पष्टीकरण पर जिला पदाधिकारी द्वारा जिस दायित्व को जांच होने से पूर्व कर लिया जाना चाहिए था, उसे जांच प्रक्रिया के क्रम में पूर्ण किया गया, जबकि यह प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं संबंधित पंचायत के पंचायत सचिव का उत्तरदायित्व था कि बैंक को भेजे गये Advice के अनुसार संबंधित लाभार्थियों को उनके खाते में राशि

चढ़ाई गई या नहीं तथा जिस उद्देश्य से सरकारी राशि दी गयी है, उस उद्देश्य की पूर्ति हो रही है या नहीं, इसका पर्यवेक्षण कर संतुष्ट होना आरोपित पदाधिकारी एवं उनके अधीनस्थ कर्मियों के दायित्व के अन्तर्गत आता है। आरोपित पदाधिकारी द्वारा समय पर दायित्व का निर्वहन नहीं रहने का प्रतिफल जाँच के क्रम में उजागर हुआ, जिसे लिखित रूप में स्वयं स्वीकार भी किया है।

निगरानी विभाग के जाँच प्रतिवेदन में भी उल्लेख किया गया है कि इंदिरा आवास के लाभार्थियों द्वारा अंचलाधिकारी को पैसे देने की बात नहीं स्वीकारी गयी। मात्र एक पंचायत के एक लाभार्थी द्वारा 5000/- रु० देने की बात बतलायी गयी, वह भी मुखिया को दिये जाने का बतलाया गया। अंचलाधिकारी एवं पर्यवेक्षण की कमी पाया गया है।

उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में श्री सुनील दत्त झा, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक-739/2011, तत्कालीन अंचलाधिकारी-सह-प्रखंड विकास पदाधिकारी, रहिका, मधुबनी सम्प्रति वरीय उप समाहर्ता, शिवहर का स्पष्टीकरण अस्वीकृत किया जाता है तथा दायित्व का निर्वहन नहीं करने/शिथिलता/पर्यवेक्षण की कमी के लिए श्री झा को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-19 के प्रावधानों के तहत नियम-14 में उल्लिखित निम्नांकित दंड उन्हें अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है:-

(क) निन्दन (वर्ष 2009-10)।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
मो० सिराजुद्दीन अंसारी,  
सरकार के अवर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 570-571+10-डी०टी०पी०।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>